वर्ष-9 | अंक 32 | 31 मार्च से 06 अप्रैल 2025 तक | पृष्ठ-12 | MPHIN/2015/63623

न्यूज क्राइम फाइल

आमंत्रण मुल्य 15/-

ग्वालियर, भिंड, मुरैना, छतरपुर, सागर, विदिशा, रायसेन, सिवनी, जबलपुर, रीवा, सतना, होशंगाबाद, हरदा एवं इंदौर में प्रसारित।

ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल व्यवस्था की जाएं : मुख्यमंत्री

समाधान ऑनलाइन में लंबित समस्याओं का हुआ समाधान 20 शासकीय सेवकों के विरूद्ध निलंबन और नोटिस जारी करने की कार्रवाई

उदय प्रताप सिंह चौहान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन में आए विभिन्न प्रकरणों में लापरवाही बरतने वाले 20 अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही पेयजल प्रदाय में अव्यवस्था के दोषी ठेकेदार को अर्थदंड से दंडित किया गया। शुक्रवार को समाधान ऑनलाइन में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों में से ऐसे प्रकरणों का समाधान किया गया जिनका लंबे समय से समाधान लंबित था। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी समाधान ऑनलाइन में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा कलेक्टर्स और अन्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समाधान ऑनलाइन में शुक्रवार को पेयजल व्यवस्था से संबंधित 3 प्रकरणों में दोषी व्यक्तियों को दंडित करने का निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिस भी जिले से नागरिकों के लिए पेयजल की व्यवस्था से जुड़ी शिकायतें प्राप्त होंगी वहां संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे। पेयजल समस्या से संबंधित एक प्रकरण में सीहोर जिले के श्री भंवर सिंह पटेल ने ग्राम पंचायत बरखेड़ी में पानी न पहुंच पाने की शिकायत की थी। इस प्रकरण में अपर मुख्य सचिव श्री संजय शुक्ला ने बताया कि ठेकेदार फर्म मेसर्स विश्वा पर 37 हजार 469 की शास्ति अधिरोपित की गई है। नल जल योजना के क्रियान्वयन में आ रही तकनीकी दिक्कतों को दूर कर घरेलू नल कनेक्शनों में जलापूर्ति प्रारंभ करवा दी गई है। इसी तरह मऊगंज के शिकायतकर्ता श्री सुनील कुमार साहू की शिकायत पर डेढ़ वर्ष से पाइप लाइन के टूट जाने से जल प्रदाय में आ रही दिक्कत को दूर कर दिया गया है। इस मामले में भी संबंधित ठेकेदार केएनके कंपनी को तत्काल कार्य करवाने के निर्देश दिए गए। इस प्रकरण में परियोजना इकाई में पदस्थ फील्ड इंजीनियर की सेवाएं समाप्त की गई है।

शिकायत का निराकरण समय पर न करने के लिए उत्तरदायी मुख्य नगर पालिका अधिकारी मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन के उपयंत्री, परियोजना प्रबंधक और सहायक परियोजना प्रबंधक को नोटिस जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी जिलों में नल-जल योजना के क्रियान्वयन में विलंब करने वालों के विरूद्ध सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने छिंदवाड़ा जिले की श्रीमती दुर्गाबाई विश्वकर्मा द्वारा कूप निर्माण के लिए समय पर कार्रवाई न करने के मामले में जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सहायक यंत्री की दो-दो वेतनवृद्धि रोकने संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी किए गया है। साथ ही गंभीर लापरवाही के दोषी ग्राम रोजगार सहायक को सेवा समाप्ति के लिए नोटिस जारी किया गया। इस प्रकरण में सचिव ग्राम पंचायत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शिकायतकर्ता को कूप निर्माण के लिए 72 हजार 372 रूपए का भुगतान करवा दिया गया है। साथ ही यह चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की शिकायत नहीं आना चाहिए वरना सख्त कार्रवाई होगी। इस प्रकरण में शिकायतकर्ता को छात्रवृत्ति की राशि 22 हजार 748 रूपए का भुगतान पोर्टल के माध्यम से कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विदिशा के श्री रोहित रैकवार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में की गई शिकायत का पर समाधान किया गया। आवेदक को दस हजार रूपए की राशि प्रदान कर दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश इस योजना में देश में अग्रणी है। इस नाते योजना के क्रियान्वयन की श्रेष्ठ स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रत्येक आवेदक का प्रकरण यथासमय स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रीवा जिले के श्री घनानंद द्विवेदी के आवेदन पर 20 हजार रूपए की राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। इस प्रकरण में आकाशीय बिजली गिरने से आवेदक द्वारा पशुधन की हानि के फलस्वरूप मुआवजा राशि का आवेदन लगभग सात महीने पहले किया गया था। इस प्रकरण में विलंब के लिए नायब नाजिर को निलंबित कर दिया गया है, साथ ही लापरवाही के दोषी तहसीलदार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

श्री रमेश जाटव को मकान की किस्त, श्री राकेश रिछारिया को आयुष्मान योजना की राशि और श्री आशाराम लोधी को गौ-संवर्धन योजना में मिला लाभ मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्वालियर के श्री रमेश जाटव की आवास योजना की राशि न मिलने के संबंध में कलेक्टर ग्वालियर को परीक्षण कर दोषी कर्मचारियों को दंडित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा सीएम हेल्पलाइन में गलत जानकारी दर्ज करने के दोषी सीएमओ को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। आवेदक श्री जाटव को आवास योजना की तीसरी किस्त की राशि का भुगतान हो गया है। इसी तरह छतरपुर के श्री राकेश कुमार रिछारिया को समाधान ऑनलाइन के माध्यम से आयुष्मान भारत योजना में 26 हजार 747 रूपए की राशि का भुगतान हो गया है। आवेदक ने 5 माह पूर्व उपचार करवाया था लेकिन अस्पताल द्वारा अनुबंध का उल्लघंन कर अनाधिकृत रूप से राशि वसूल की गई।

विवाह योजना, छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्राकृतिक आपदा पर मुआवजा राशि के प्रकरण भी हुए हल

समाधान ऑनलाइन में खंडवा जिले के श्री दिनेश कलमे ने निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना में राशि मिलने में हुई देर की शिकायत की थी। समाधान ऑनलाइन में यह मामले आने के बाद गत 21 मार्च को कलमे दंपति को एक लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि का भुगतान हो गया है। इस प्रकरण में लापरवाही बरतने पर सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक, जिला कोषालय अधिकारी और निःशक्त कल्याण शाखा के प्रभारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं। साथ ही सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जनपद पंचायत खालवा को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंगरौली जिले की सुश्री मोनिका द्वारा छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान समय पर न किए जाने की शिकायत पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इस प्रकरण में पोर्टल संचालन करने वाले अधिकारियों को भविष्य में गंभीरतापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए।

कर्मा बाई जयंती के अवसर पर उन्हें नमन। उनकी अद्वितीय सेवा, संघर्ष और समर्पण को हमेशा याद किया जाएगा।
गोपाल भार्गव -विधायक रहली, पूर्व मंत्री

1584 करोड़ में 10 लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी

स्व सहायता समूह की महिलाओं को सालाना 1 लाख आमदनी दिलाने की है स्कीम

न्यूज क्राइम फाइल

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई लाड़ली बहना योजना में महिलाओं को 3 हजार रुपए देने की मांग को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि सरकार अब बहनों को लखपति दीदी बनाने की दिशा में काम कर रही है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में पता चला कि मध्यप्रदेश में पिछले तीन सालों में 1,584.22 करोड़ रुपए खर्च कर 10 लाख 51 हजार 69 महिलाएं लखपति दीदी घोषित की गई हैं। हालांकि, सरकार ने इन्हें स्वघोषित लखपति दीदी बताया है।

आजीविका मिशन के फंड से होता है खर्च

राज्यसभा में दिए गए जवाब में बताया गया कि लखपति दीदी योजना के लिए अलग से कोई बजट आवंटन नहीं किया गया है। लखपति दीदी योजना के सभी कार्यकलाप जैसे प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, प्रारंभिक वित्तपोषण सहित वित्तीय सहायता, डे-एनआरएलएम योजना से वित्त पोषित है। अतिरिक्त वित्तीय जरूरतों के लिए स्व सहायता समूहों के सदस्यों को बैंक लिंकेज और बैंक ऋण के माध्यम से सहायता दी जाती है। अब

तक 1 करोड़ 15 लाख स्व सहायता समूह की महिलाएं लखपति बहना बन चुकी हैं।

जानिए लखपति दीदी योजना है क्या?

स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाओं की सालाना आय एक लाख रुपए से अधिक या मासिक आय 10 हजार रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। यह आय कम से कम चार कृषि मौसम (चार फसलों) या चार व्यवसायिक चक्रों तक लगातार बनी रहनी चाहिए। सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे-एनआरएलएम) के तहत महिला समूहों को दो प्रकार के क्लस्टरों के रूप में प्रोत्साहित कर रही है। पहली कारीगर क्लस्टर (हथकरघा और हस्तशिल्प), दूसरी क्षेत्रीय क्लस्टर (खाद्य सेवा, पर्यटन, पोषण आदि)। इस योजना के तहत डिजाइन विकास, गुणवत्ता आश्वासन, उद्यम निर्माण, बाजार विकास, वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर भी काम किया जाता है। इस पहल में सामूहिक उद्यमों के विकास, सामान्य सुविधा केंद्र (ष्टस्नष्ट) और सामान्य उत्पादन केंद्र के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों को समर्थन दिया जाता है। प्रत्येक क्लस्टर में, हस्तक्षेप की अवधि के दौरान कम से कम 100 सूक्ष्म उद्यमों को शामिल करने की क्षमता होती है। प्रत्येक क्लस्टर की स्थापना और संचालन के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, स्त्ररूरू (राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन) और तकनीकी सहायता एजेंसियां मौजूदा सरकारी योजनाओं जैसे- पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि योजना (स्स्नक्रञ्जद्क), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) और विकास आयुक्त (हथकरघा) की योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इस बार बजट में भारत सरकार ने एक योजना बनाई है। वो योजना दो साल के लिए है। वो योजना ऐसी है, जो बहनें बैंक में कुछ पैसे जमा कराएगी, एफडी कराएगी तो उनको अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। सिर्फ बहनों के लिए विशेष ब्याज की योजना से दो साल के लिए एक स्कीम बनाई है।

अधिकारी नहीं आए तो भोपाल सांसद ने मीटिंग छोड़ी

न्यूज क्राइम फाइल

भोपाल में एक बैठक में नगर निगम कमिश्नर के नहीं आने से नाराज सांसद आलोक शर्मा बैठक छोड़कर चले गए। अधिकारी ने उनका फोन तक नहीं उठाया। सांसद ने नगर निगम अधिकारियों के रवैये पर सख्त एतराज जताते हुए इसे भोपाल की जनता और जनप्रतिनिधियों का अपमान बताया। वहीं निगम कमिश्नर ने कहा कि उन्हें बैठक की कोई सूचना नहीं थी। दरअसल, भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने शुक्रवार को पहली बार जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की मीटिंग ली। जिसमें सबसे पहले बिजली कंपनी की समीक्षा की गई। इसमें कई काम अधूरे पाए गए। इसके बाद जल संसाधन विभाग की समीक्षा में भी अधिकारी नदारद रहे। जिस पर सांसद ने उन्हें नोटिस देने की बात कही। नगर निगम की समीक्षा में भी यही हालात बने तो सांसद भड़क गए। इसके लिए जब नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण यादव के बारे में पूछा गया तो बताया गया कि वे नहीं है। जब पूछा कि उनकी जगह कौन आया है तो बताया गया कि कोई नहीं है। इसके बाद सांसद, महापौर और विधायक भगवान दास सबनानी ने नगर

निगम कमिश्नर को फोन लगाया। लेकिन, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इससे नाराज होकर सांसद आलोक शर्मा ने बैठक स्थगित कर दी।

सांसद बोले- ये भोपाल की 35 लाख जनता का अपमान

सांसद आलोक सांसद ने कहा कि नगर निमग कमिश्नर का बैठक में नहीं आना भोपाल की 35 लाख आबादी का अपमान है। वे विधायक और महापौर का काल भी नहीं उठा रहे हैं। दरअसल, बैठक में स्मार्ट सिटी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर बात होनी थी। बैठक में विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर मालती राय, जिला पंचायत अध्यक्ष रामकुंवर बाई गुर्जर, उपाध्यक्ष मोहन जाट, सीईओ इला तिवारी समेत जिला अधिकारी मौजूद थे।

बैठक के बाद सांसद आलोक शर्मा ने कहा-

कुछ अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण आज की बैठक हमने स्थगित कर दी है। शीघ्र ही जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर बैठक करेंगे।

जनप्रतिनिधियों से मिलने पहुंचे कलेक्टर

बैठक स्थगित होने के बाद नाराज जनप्रतिनिधियों से कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह मिलने पहुंचे। जिला पंचायत अध्यक्ष के रूम में सांसद, विधायक, महापौर से कलेक्टर की बात हुई। करीब आधे घंटे चली बंद कमरे की इस बातचीत के बाद सभी जनप्रतिनिधि चले गए।

बिजली कनेक्शन काटने और पानी का बड़ा मुद्दा

भोपाल के गांवों में बिजली कनेक्शन काटने और पानी का बड़ा मुद्दा था। इसी मुद्दे पर गुरुवार को हुई जिला पंचायत साधारण सभा की मीटिंग में जिपं उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट, सदस्य विनय मेहर, फंदा जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत ने अफसरों पर जमकर नाराजगी जताई थी। शुक्रवार को भी इस मुद्दे को लेकर बात हो सकती थी।

इंजीनियर पर भड़के थे जनप्रतिनिधि

गुरुवार को उपाध्यक्ष जाट, सदस्य विनय मेहर ने बिजली कनेक्शन काटने और गांवों के अंधेरे में डूबे रहने का मुद्दा उठाया था। जाट भी गांवों में पेयजल के मुद्दे पर इंजीनियर संजय सक्सेना पर भड़के थे।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की प्रेरणा से युवाओं की भूमिका को रेखांकित करने एवं उनमें

योगी आदित्यनाथ- मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश

भोपाल में प्रेम प्रसंग में युवक ने किया सुसाइड

प्रेमिका की दोस्त से कॉल पर कहा- जहरीली गोली खा लूंगा; परिजन बोले-प्रेमिका प्रताड़ित करती

न्यूज क्राइम फाइल

भोपाल के ऐशबाग में रहने वाले एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले उसका अपनी गर्लफ्रेंड से विवाद हुआ था। युवक के मोबाइल में परिजनों को विवाद की ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है, जिसमें गर्लफ्रेंड की दोस्त उसे जानकारी देती है कि प्रेमिका ने हाथ की नस काट ली है और गुस्से में है। परिजनों का कहना है कि हम शादी के लिए तैयार थे, लेकिन इस घटना ने सभी को झकझोर दिया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। युवक ने शुक्रवार की रात जहर खा लिया था और शनिवार तड़के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शनिवार दोपहर पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

उल्टियां करने लगा तो पिता से कहा, जहर खा लिया

शाकिर अली (30), पुत्र रहबर अली, निवासी अहमद अली कॉलोनी, ऐशबाग, भारत टॉकीज पर स्थित उजैर पर ऑटो डीलिंग का काम करता था। युवक के जीजा शाहिद अली ने बताया कि शुक्रवार रात शाकिर जहरीला पदार्थ खाकर घर लौटा। जब उसने उल्टियां करनी शुरू कीं, तो उसके पिता ने उससे बात की। तब शाकिर ने खुद बताया कि उसने जहर खा लिया है और कहा, ऑटो डील के मालिक उजैर भाई

शाकिर, मृतक

को कॉल कर दो, वे मुझे अस्पताल ले जाएंगे। शाहिद ने आगे बताया कि पिता ने मुझे कॉल कर इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद मैं तुरंत शाकिर को हमीदिया अस्पताल लेकर गया, जहां कई घंटे इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। शाहिद ने बताया कि शाकिर का ऐशबाग में रहने वाली एक युवती से प्रेम संबंध था। युवती छोटी-छोटी बातों को लेकर शाकिर पर दबाव बनाती थी और जब वह बात नहीं मानता, तो हाथ की नस काटने और आत्महत्या करने की धमकी देती थी। शाहिद का दावा है कि यही प्रताड़ना शाकिर की आत्महत्या की वजह बनी।

मोबाइल में मिलीं कॉल रिकार्डिंग्स शाहिद ने कहा कि शाकिर के मोबाइल में कई ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली हैं। एक रिकॉर्डिंग में गर्लफ्रेंड की दोस्त शाकिर से कहती है, इसे (प्रेमिका) समझाओ, वह हाथ की नस काट रही है और खुद को नुकसान पहुंचा रही है। इसके जवाब में शाकिर कहता है, इनका गुस्सा ही सब खराब कर रहा है। गुस्से में इसे कुछ समझ नहीं आता। एक अन्य ऑडियो में प्रेमिका खुद कॉल पर कहती है, मैं चार बजे तक घर जा रही हूं। अगर घर जाने के बाद कॉल नहीं उठाऊं, तो घर आ जाना और मुझे ले जाना। मेरा दिल घबरा रहा है, अब और सहन नहीं कर सकती। बहुत परेशान हो चुकी हूं।

युवक के सुसाइड करने की बात की रिकॉर्डिंग भी सामने आई

एक और ऑडियो में दूसरी युवती शाकिर से कहती सुनाई दे रही है, प्रेमिका ने कमरे का गेट बंद कर लिया है और वह दरवाजा नहीं खोल रही है।

इस पर शाकिर गुस्से में जवाब देता है,

उसे दस मिनट में गेट खोलने के लिए बोलो। नहीं तो मेरे पर्स में जो जहरीली गोली रखी है, उसे निकालकर खा लूंगा। जान देना क्या होता है, मैं बताऊंगा। मैं मर ही जाऊंगा। मैं प्रेमिका से बात करती हूं।

युवती के भाई पर भी मारपीट के आरोप

शाहिद ने बताया कि तीन-चार दिन पहले प्रेमिका के भाई ने शाकिर को घर बुलाकर बुरी तरह पीटा था। शाकिर को कमरे में बंद कर मारा गया था, लेकिन इसकी शिकायत थाने में दर्ज नहीं कराई गई थी। शाहिद ने कहा, हमें उनकी शादी से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन लड़की के घरवाले राजी नहीं थे। खुद लड़की भी साले पर गुस्सा करती थी। मृतक शाकिर के पिता कैंसर पीड़ित हैं और लास्ट स्टेज पर हैं। बेटे की आत्महत्या के बाद वे गहरे सदमे में चले गए हैं। शाकिर की तीन बहनें हैं, जिनकी शादी हो चुकी है और उसका एक बड़ा भाई मेहशर अली है।

सलमान के राम मंदिर वाली घड़ी पहनने पर भड़के मौलाना

कहा- शरीयत का गुनहगार; भाजपा विधायक बोले- राम सबके, उन्हें हिंदुओं ने सिर पर बैठाया

न्यूज क्राइम फाइल

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की राम मंदिर स्पेशल एडिशन घड़ी पहनने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इसे शरीयत के खिलाफ बताते हुए सलमान को गुनहगार करार दिया है। इधर, भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा ने सलमान खान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि राम सबके हैं। जो राम लोगों के दिलों में हैं, उन्हें नमन करने में किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। हर सलमान-रसखान बनने के लिए आतुर है।

राम हर हिंदुस्तानी के दिल में बसे हैं

भाजपा विधायक शर्मा ने कहा कि राम मंदिर और भगवान राम की छवि भारत के लोगों के दिलों में बसी है। इसे नमन करने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राम से अलग न तो हिंदुस्तान को किया जा सकता है, न ही हिंदुस्तानियों को। उन्होंने कहा कि सलमान खान जैसे मुस्लिम सेलेब्रिटीज ने देश की शान बढ़ाई है, जबकि कुछ मौलवी सिर्फ विवाद

फैलाते हैं। आज एक मौलवी चला जाए तो चार मुसलमान कंधा नहीं देते, लेकिन सलमान के पीछे लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। हिंदुओं ने सलमान को सिर पर बैठाया है।

मां ने दी थी सलमान को स्पेशल एडिशन घड़ी

सलमान खान हाल ही में अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म सिकंदर के प्रमोशन के दौरान इस घड़ी में नजर आए थे, जो उनकी मां ने उन्हें गिफ्ट की थी। बताया जा रहा है कि इस घड़ी की कीमत 34 लाख रुपए है और दुनिया में इसकी सिर्फ 49 यूनिट्स ही बनी हैं।

मौलाना ने कहा था- सलमान को खुदा के यहां मुंह दिखाना है

मौलाना शहाबुद्दीन बोले- सलमान एक मशहूर मुसलमान हैं। लाखों की तादाद में उनके चाहने वाले हैं। सलमान ने राम मंदिर के प्रचार के लिए बनाई गई घड़ी पहनी। किसी भी मुसलमान को शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो गैर-मुस्लिमों के मंदिरों का प्रचार करें। अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है तो वह शरीयत का मुजरिम है। ये नाजायज और हराम है, बाज आना चाहिए। मैं सलमान खान को नसीहत देना चाहता हूं कि वो अपने हाथों से राम मंदिर की घड़ी उतार दें और जो कुछ भी शरीयत के खिलाफ काम किया है उससे तौबा कर लें। क्योंकि उनको खुदा के यहां मुंह दिखाना है। अपना हिसाब-किताब करना है। वो एक अच्छे मुसलमान होने का सबूत पेश करें।

कमाल राशिद ने कहा- मुस्लिमों का मजाक उड़ा रहे सलमान

कमाल राशिद खान ने अपने ऑफिशियल ङ्क प्लेटफॉर्म पर लिखा है- उन सभी मुस्लिमों को मुबारकबाद जो ईद पर सलमान खान की सिकंदर देखकर उन्हें ईदी देना चाहते हैं। वो राम जन्मभूमि एडिशन की जियोनिस्ट को. वॉच पहनकर सभी मुस्लिमों का मजाक उड़ा रहे है।

संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को राजकीय अवकाश घोषित करने हेतु पीएम श्री @narendramodiजी का कोटिश- आभार।
वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष - भाजपा मप्र

आलेख

अगले साल तक कैसे खत्म हो पाएगा लाल आतंक

इसे संयोग कहें या कुछ और, बीते 21 मार्च को जब छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में सुरक्षा बलों के हाथों तीस नक्सली मारे गए, उसी वक्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संसद में नक्सलवाद के सफाए का ऐलान कर रहे थे। अमित शाह का कहना था कि अगले 375 दिनों में नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। अगर तारीखों के हिसाब से कहें तो केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक कभी लाल आतंक के नाम से कुख्यात रहे नक्सलवाद के सफाए का लक्ष्य रखा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच नक्सलवाद आखिरी सांसे ले रहा है और जल्द ही आतंक का पर्याय रही ये विचारधारा अतीत बन जाएगी। साल 2025 के अभी तीन महीने ही गुजरे हैं, लेकिन इस बीच नक्सलवाद को लेकर जो आंकड़े सामने हैं, उनसे तो लगता यही है कि नक्सलवाद अब गिने-चुने दिनों की ही बात है। केंद्रीय गृहमंत्रालय के आंकड़ों पर भरोसा करें तो बीते तीन महीनों में ही सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 119 नक्सली मारे जा चुके हैं। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को यह कामयाबी सिर्फ 10 मुठभेड़ों में ही मिली हैं। बीते साल यानी 2024 में मुठभेड़ों में 239 नक्सली मारे गए थे। यानी सिर्फ सवा साल की अवधि में ही 358 नक्सली मारे जा चुके हैं। इतने नक्सलियों का मारे जाने और भारी संख्या में नक्सलियों के आत्म समर्पण करने का संकेत साफ है कि अब नक्सलियों की कमर टूटती जा रही है। शायद यही वजह है कि अमित शाह संसद में पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐलान कर रहे हैं कि नक्सलवाद देश में आखिरी सांसे गिन रहा है। साल 2010 के आंकड़ों के हिसाब से देश के तकरीबन छठवें हिस्से में नक्सलवाद का प्रभाव था। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक नक्सलवाद फैला हुआ था। गृहमंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से तब देश के 96 जिलों में आतंकवाद का खूनी पंजा फैला हुआ था। यूं तो हर सरकार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाती रही है, लेकिन इसमें तेजी केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद आई। नक्सलवाद को ज्यादातर सरकारें कानून और व्यवस्था का मामला मानती रहीं, उसके जिम्मेदार सामाजिक कार्यों को किनारे रखा जाता रहा। मोदी सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था का मामला तो माना, लेकिन उसके साथ ही इसे सामाजिक नजरिए से भी देखना शुरू किया। नक्सलवाद को लेकर कहा जाता रहा है कि जहां विकास नहीं पहुंचा, जहां शोषण की अर्थव्यवस्था रही, वहीं नक्सलवाद को पनपने का ज्यादा मौका मिला। शायद इसी वजह से नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के पहिये को तेजी से दौड़ाने की तैयारी हुई। सड़कों और रेल लाइन की पहुंच नक्सल प्रभावित इलाकों में बढ़ाने की शुरूआत हुई। बीते आठ वर्षों में 10718 करोड़ की लागत से नक्सल प्रभावित इलाकों में करीब 9356 किमी सड़कों का निर्माण किया गया। इन इलाकों में तैनात केंद्रीय बलों तैनात केंद्रीय बलों द्वारा स्थानीय आबादी के लिए जहां स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने शुरू हुए, वहीं उन्हें मुफ्त में जरूरी दवाएं दी जाने लगीं। इसी तरह उन इलाकों में पेयजल सुविधा बढ़ाने, सोलर लाइट की सुविधा देने के साथ ही खेती के उपकरण और बेहतर बीच आदि देने की कोशिश तेज हुई। गृहमंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, साल 2014 से अब तक इन मदों में नक्सल प्रभावित इलाकों में करीब 140 करोड़ रुपये के काम किए जा चुके हैं। डाक विभाग ने 90 नक्सलप्रभावत प्रभावित जिलों में, तकरीबन हर तीन किलोमीटर पर सिर्फ आठ वर्षों में ही 4903 नए डाकघर खोले हैं। इसी तरह अप्रैल-2015 से लेकर अब तक 30 सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में 1258 नई बैंक शाखाएं और 1348 एटीएम लगाए गए हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में संचार की सुविधा बढ़ाने के लिए पहले चरण में 4080 करोड़ रूपये की

लागत से 2343 मोबाइल टावर लगाए गए तो दूसरे चरण में 2210 करोड़ से 2542 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इन इलाकों में 245 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाने की तैयारी है,जिनमें 121 काम शुरू कर चुके हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि नक्सल उग्रवाद ऐसे क्षेत्रो में तेजी से पनपा, जहां गरीबी ने जड़ें जमा रखी थी। नक्सली विचार प्रभवित समूहों ने इन इलाकों के लोगों के असंतोष को खाद पानी के रूप में इस्तेमाल किया और इस तरह उग्रवाद को बढ़ावा मिला। इन समूहों को स्थानीय समर्थन मिलने के कारण सुरक्षा संस्थाओ को अपना काम करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, परन्तु 2014 के बाद हालात बदले। दूसरी तरफ उग्रवादी समूहों को हो रही फंडिंग पर रोक लगाने के लिए चौकसी बढ़ाई गई। इसके तहत नक्सल प्रभावित राज्यों ने जहां 22 करोड़ की संपत्ति जब्त की,वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने तीन और एनआईए ने पांच करोड़ की संपत्ति जब्त की। नक्सली हिंसा की जांच के लिए एनआईए में अलग से एक सेक्शन बनाया गया। जिसे अब तक 55 मामलों की जांच सौंपी जा चुकी है। इसी तरह विशेष कार्रवाई के लिए विशेषज्ञ सुरक्षा बलों पर जोर दिया गया और सूचनाओं को साझा करने का नेटवर्क विकसित किया गया। नक्सलरोधी ऑपरेशन के लिए केंद्रीय और राज्यों विशेष ऑपरेशन टीमें बनाई गईं। सुरक्षा बलों और नक्सलियों पर निगाह के लिए तकनीक को बढ़ावा भी दिया गया। इसके तहत लोकेशन मोबाइल फोन और दूसरी तकनीक सुरक्षा बलों को मुहैया कराई गईं। द्रोण कैमरों से नक्सलियों पर निगाहबानी शुरू हुई और कैजुअल्टी या विशेष ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई। शायद यही वजह रही कि संसद में नक्सल ऑपरेशन को लेकर गृहमंत्री अमित शाह बेहद आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रमुख जगहों पर सीआरपीएफ और इसकी विशेष इकाई %कोबरा% ही माओवादियों से लोहा ले रही है। इन बलों ने ऐसी रणनीति बनाई है, जिसमें नक्सलियों के पास दो ही विकल्प, सरेंडर करो या गोली खाओ, बचे हैं। अब ऐसा कोई इलाका नहीं बचा है, जहां सुरक्षा बलों की पहुंच न हो।

सम्पादकीय

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बढ़ते कदम

दिनांक 21 से 23 मार्च तक बंगलूरू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में दशहरा के पावन पर्व पर हुई थी, और इस प्रकार संघ अपनी स्थापना के 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है एवं इस वर्ष दशहरा के शुभ अवसर पर ही अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर लेगा। संघ की स्थापना विशेष रूप से भारतीय हिंदू समाज में राष्ट्रीयत्व का भाव जागृत करने एवं हिंदू समाज के बीच समरसता स्थापित करने के लक्ष्य को लेकर हुई थी। इन 100 वर्षों के अपने कार्यकाल में संघ ने हिंदू समाज को एकजुट करने में सफलता तो हासिल कर ही ली है साथ ही विशेष रूप से समाज की सज्जन शक्ति में राष्ट्रीयत्व का भाव पैदा करने में सफलता अर्जित की है। सज्जन शक्ति समाज की वह शक्ति है कि जिनकी बात समाज में गम्भीरता से सुनी जाती है एवं उस पर अमल करने का प्रयास भी होता है। संघ ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु शाखाओं की स्थापना की थी। इन शाखाओं में देश की युवा पीढ़ी में राष्ट्रीयत्व का भाव जगाकर ऐसे स्वयंसेवक तैयार किए जाते हैं जो समाज के बीच जाकर देश के आम नागरिकों में राष्ट्र भावना का संचार करते हैं एवं समाज के बीच समरसता का भाव पैदा करने का प्रयास करते हैं। संघ द्वारा स्थापित की गई शाखाओं की कार्यपद्धति पर आज विश्व के अन्य कई देशों में शोध कार्य किए जाने के बारे में सोचा जा रहा है कि किस प्रकार संघ द्वारा स्थापित इन शाखाओं से निकला हुआ स्वयंसेवक समाज परिवर्तन में अपनी महती भूमिका निभाने में सफल हो रहा है और पिछले लगातार 100 वर्षों से इस पावन कार्य में संलग्न है। हाल ही में, दिनांक 14 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक (44 दिन) प्रयागराज में लगातार चले एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए महाकुम्भ के मेले में पूरे विश्व से 66 करोड़ से अधिक हिंदू धर्मावलम्बियों ने पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। इतनी भारी संख्या में हिंदू समाज कभी भी किसी महान धार्मिक आयोजन में शामिल नहीं हुआ होगा और संभवत- पूरे विश्व में कभी भी इस तरह का आयोजन सम्पन्न नहीं हुआ होगा। इस महाकुम्भ में समस्त हिंदू समाज एकजुट दिखाई दिया, न किसी की जाति, न किसी का मत, न किसी के पंथ का पता चला। बस केवल सनातनी हिंदू हैं, यही भावना समस्त श्रद्धालुओं में दिखाई दी। इसी का प्रयास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्षों से करता आ रहा है। संघ द्वारा आज न केवल भारतीय हिंदू समाज को एकता के सूत्र में पिरोए जाने का कार्य किया जा रहा है बल्कि पूरे विश्व में अन्य देशों में निवासरत भारतीय मूल के हिंदू समाज के नागरिकों को भी एक सूत्र में पिरोए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

जिस घर ने अपना कमाने वाला खो दिया, उस घर के पीड़ितों की सुनवाई करने की बजाय @DrMohanYadav सरकार की पुलिस उसकी बूढ़ी मां को मार रही है!
जीतू पटवारी अध्यक्ष, मप्र कांग्रेस

डिप्टी कलेक्टर पर महिलाओं से अभद्रता के आरोप, सस्पेंड

नर्मदापुरम में हाईकोर्ट से स्टे लाए थे, कमिश्नर ने दिए निलंबन के आदेश

न्यूज क्राइम फाइल

नर्मदापुरम के डिप्टी कलेक्टर पर महिला कर्मचारियों से अभद्र भाषा में बात करने और गलत मैसेज भेजने के आरोप हैं। शिकायत के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, कमिश्नर के.जी. तिवारी ने शुक्रवार देर शाम डिप्टी कलेक्टर असवान राम चिरामन के सस्पेंशन के आदेश जारी किए। बताया जा रहा है कि कलेक्टर की जांच में महिला कर्मचारियों और पटवारियों के बयान लिए गए थे। इसी के बाद डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इधर, असवान राम चिरामन ने सभी आरोपों को झूठा बताया है। उनका कहना है कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बता दें, इससे पहले भी चिरामन विवादों में रह चुके हैं। सिंगरौली जिले के चितरंगी में एसडीएम रहने के दौरान उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वे एक महिला से जूते के लेस बंधवाते नजर आ रहे थे। उस वक्त मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें तत्काल हटा दिया था। इसके बाद वह नर्मदापुरम में पदस्थ किए गए

हाईकोर्ट से स्टे लाए, फिर भी निलंबित हुए

असवान राम चिरामन सोहागपुर में एसडीएम के पद पर पदस्थ थे। शिकायतें मिलने पर 21 मार्च को उन्हें पद से हटा दिया गया था। उन्होंने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और 25 मार्च को स्टे ले आए। हालांकि, इस दौरान प्रशासन ने जांच जारी रखी और महिला कर्मचारियों के बयान दर्ज किए। जांच रिपोर्ट के आधार पर कमिश्नर के.जी. तिवारी ने डिप्टी कलेक्टर को निलंबित करने का आदेश दिया।

असवान राम चिरावन

पटवारी संघ ने पिछले महीने भी की थी शिकायत

डिप्टी कलेक्टर चिरामन पिछले महीने पटवारी संघ से भी विवाद में रहे। उन्होंने कुछ पटवारियों का इंक्रीमेंट रोक दिया था, जिससे संघ नाराज हो गया और हड़ताल की चेतावनी दी थी। पटवारी संघ के विरोध के बाद चिरामन को झुकना पड़ा और उन्होंने आदेश वापस ले लिया था।

चिरामन बोले- मैं निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं

डिप्टी कलेक्टर असवान राम चिरामन ने कहा, मैं पिछले आठ महीने से सोहागपुर में एसडीएम के पद पर रहा, मैंने अच्छा काम किया। इस दौरान केवल दो-तीन बार पटवारियों की बैठक ली। यह झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि मैं उन्हें बैठक में डांटता था। मैं सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक काम करता हूं। अनुशासन और कार्यशैली में सख्ती रखना मेरे स्वभाव में है, लेकिन यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। राजस्व महाअभियान के दौरान दिए गए लक्ष्यों को मैंने पूरा करने के लिए सख्ती बरती। इससे कुछ लापरवाह और कामचोर कर्मचारियों पर कार्रवाई करनी पड़ी। इस कारण पटवारी संघ मेरे विरोध में उतर आया। मुझे जानकारी मिली कि नायब तहसीलदार नीरू जैन ने तहसीलदार की ओर से कलेक्टर को एक शिकायत पत्र भेजा है। इसमें तहसीलदार की सील का उपयोग किया गया। मैं निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। 22 मार्च को सोहागपुर से हटाने का आदेश जारी किया गया, जिसकी सूचना अगले दिन रविवार को मिली। इसके बाद हाईकोर्ट से स्टे आदेश लिया और 26 मार्च को कलेक्टर कार्यालय में जमा किया। 28 मार्च, शुक्रवार को सोहागपुर एसडीएम के पद पर बहाल करने का आदेश जारी हुआ, लेकिन उसी दिन देर शाम निलंबन की सूचना मिली।

कमिश्नर बोले- रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई

नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर कृष्ण गोपाल तिवारी ने कहा कि सोहागपुर के एसडीएम असवान राम चिरामन को नर्मदापुरम कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि चिरामन द्वारा आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग को लेकर यह कार्रवाई की गई है। कलेक्टर की रिपोर्ट में पूरे घटनाक्रम का विस्तार से उल्लेख किया गया है।

कार्रवाई पर कांग्रेस नेता का तंज

कमिश्नर की इस कार्रवाई पर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह पटेल ने सोशल मीडिया पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि सोहागपुर एसडीएम ने क्या चंदा नहीं दिया था इसलिए रातोंरात ट्रांसफर और जब न्यायालय से स्टे मिला तो जॉइनिंग कराकर निलंबित कर दिया गया, अब चंदा किसी का भी हो सकता है? बुरा न मानना होली है।

पत्रकार बनने का सुनहरा अवसर

अगर आपके अंदर लिखने का कौशल है और पत्रकारिता में रुचि है, तो 'न्यूज क्राइम फाइल' को आपकी तलाश है। 'न्यूज क्राइम फाइल' से जुड़ कर आप हर माह दस हजार रुपये तक कमा सकते हैं। 'न्यूज क्राइम फाइल' भोपाल, ग्वालियर, सतना, सागर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर और नीमच में ब्यूरो ऑफिस खोलने जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार तत्काल हमें अपना बॉयोडाटा मेल करें या व्हाट्सअप करें।

उदय प्रताप सिंह चौहान (संपादक) 07223003441

website: www.newscrimefile.com

email: newscrimefile@yahoo.com

जनसेवा और सुशासन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जन-जन के जीवन में खुशहाली और बदलाव का संकल्प है।

मोहन यादव- सीएम मप्र

विश्वविद्यालयों में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम से संवारेंगे भविष्य

मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले- प्रदेश के विश्वविद्यालय सशक्त हो रहे

न्यूज क्राइम फाइल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालय लगातार सशक्त हो रहे हैं और आने वाले समय में आर्थिक रूप से समर्थ और सक्षम बनेंगे। उच्च शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सरकार विश्वविद्यालयों को रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित कर रही है। बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय के ज्ञान विज्ञान भवन में आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज आरंभ करें, राज्य सरकार इन कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों की व्यवस्था करेगी। इन अस्पतालों के कर्मचारियों के वेतन-भत्तों का भार सरकार उठाएगी, जबकि विश्वविद्यालय शिक्षण और परीक्षा संबंधी कार्यों का संचालन करेंगे। परीक्षा शुल्क का उपयोग मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालयों के विकास में किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्वविद्यालयों को डेयरी टेक्नोलॉजी, कृषि और अन्य व्यवसायिक दक्षता वाले नए पाठ्यक्रम शुरू करने की सलाह दी, जिससे विद्यार्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।

शासकीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शासकीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कर्मचारी और पेंशनर्स भी वेतन एवं भत्तों में वृद्धि का लाभ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि, प्रदेश में अब केवल दो श्रेणियों के विश्वविद्यालय हैं। निजी और शासकीय। उच्च शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में नए-नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत की जा रही है, जिससे शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को वर्ष प्रतिपदा और गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं दीं।

पेंशनर्स समितियों को वित्तीय सहायता

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शासकीय विश्वविद्यालयों की दो पेंशनर्स समितियों को एक-एक लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के प्रति संवेदनशील है और उनके हित में लगातार निर्णय ले रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का विश्वविद्यालयों के पेंशनर्स, अधिकारी, शिक्षक और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से सम्मान और अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को वृहद पुष्पहार, अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। समारोह में मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के संचालक अशोक कड़ैल, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. एस.के. जैन, कुल सचिव प्रो. मंसूरी, प्रो. कालिका यादव, प्रो. गोपाल शर्मा सहित कई गणमान्य उपस्थित थे।

सौजन्य भेंट

उपमुख्यमंत्री देवड़ा ने वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप-2025 में अपनी असाधारण प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से स्वर्ण पदक जीतने वाले मध्यप्रदेश के बेटे रोहित सिंह जी से स्नेहपूर्ण भेंट कर उनकी स्वर्णिम सफलता के लिए हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी।

भारतीय संस्कृति के बारे में दुनिया की जिज्ञासा लगातार बढ़ रही है, और कैसमै जैसे लोगों ने इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।
प्रधानमंत्री- नरेंद्र मोदी

स्वीटी बूरा केस में पति के वकील सामने आए

बोले- दीपक हुड्डा दूसरे महंगे खिलाड़ी थे, बॉक्सर ने तसले में नहाने की बात की थी

न्यूज क्राइम फाइल

हरियाणा में हिसार की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बूरा के आरोपों पर उनके पति व कबड्डी टीम के पूर्व कैप्टन दीपक हुड्डा के वकील ने जवाब दिया है। हुड्डा के वकील सागर पंघाल ने कहा कि 2014 में प्रो-कबड्डी लीग में दीपक हुड्डा दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी थे। स्वीटी बूरा ने कहा था कि दीपक इतना गरीब था कि तसले में नहाता था। दीपक वेलेंटाइन डे पर भी गिफ्ट लेकर गया था, लेकिन स्वीटी बूरा नहीं मानीं। वहीं स्वीटी बूरा के दीपक का लड़कों में इंटरेस्ट के बयान पर वकील ने कहा कि दोनों ने 7 साल तक एक-दूसरे को डेट किया। लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे। तब स्वीटी ने ये बात क्यों नहीं कही। स्वीटी से परेशान होकर एक बार तो दीपक हुड्डा के मन में भी इंजीनियर अतुल सुभाष जैसे सुसाइड के ख्याल आ रहे थे। हालांकि दोस्तों ने मिलकर उसे समझाया। स्वीटी बूरा ने पति दीपक हुड्डा के खिलाफ हिसार में दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा रखा है। वहीं दीपक हुड्डा ने रोहतक में प्रॉपर्टी हड़पने का केस दर्ज करवा रखा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हिसार के महिला थाने में दीपक हुड्डा से मारपीट को लेकर स्वीटी बूरा पर एक और केस दर्ज हुआ है। जिसका वीडियो आने के बाद स्वीटी बूरा ने दीपक हुड्डा पर कई आरोप लगाए थे।

1. शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में थे दोनों

दीपक हुड्डा के वकील ने दोनों के रिश्तों के बारे में खुलासा किया कि स्वीटी बूरा और दीपक हुड्डा शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहा करते थे। 2015 से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इतने साल रिलेशनशिप में रहने के बाद 2022 में दोनों ने शादी की। अगर दीपक हुड्डा को लड़कों में इंटरेस्ट होता तो स्वीटी इस बात को आज क्यों बता रही है।

2. प्रो-कबड्डी में सेकेंड हाईएस्ट बिके थे हुड्डा

स्वीटी बूरा ने हिसार में प्रेस कान्फ्रेंस में कहा था कि दीपक हुड्डा गरीब परिवार से हैं और वह तसले में नहाकर बड़ा हुआ है। इस पर दीपक के वकील सागर ने कहा कि दीपक हुड्डा जमीन से उठकर आज इस मुकाम तक पहुंचा है। जहां तक गरीबी की बात है तो वह 2014 में प्रो कबड्डी में बिकने वाले खिलाड़ियों में सेकेंड हाईएस्ट प्लेयर में था। दीपक को तेलगु टाइटंस ने 12.6 लाख में खरीदा था। पहले नंबर वाले की बोली 12.80 लाख की लगी थी।

3. सुलह की कई बार कोशिश की,

वकील सागर ने बताया कि जब स्वीटी बूरा दीपक हुड्डा को छोड़कर हिसार आकर रहने लगी थी तो दीपक हुड्डा वेलेंटाइन डे पर उससे मिलने गिफ्ट लेकर गया था। वह चाहता था कि दोनों के बीच कड़वाहट खत्म हो जाए। मगर, स्वीटी बूरा नहीं मानी। दीपक ने अपने स्तर पर उसे मानने की पूरी कोशिश की और पब्लिक में उसके खिलाफ कभी गलत नहीं कहा। स्वीटी से झगड़े के बाद दीपक हुड्डा डिप्रेशन में चला गया था। वह मुझसे और दोस्तों से कहता था कि मेरे साथ अतुल सुभाष केस की तरह ना हो जाए। इस पर हमने उसे संभाला और समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वह अब इन चीजों से धीरे-धीरे बाहर आ रहा है।

4. मारपीट का वीडियो एडिटेड नहीं असली

हिसार के महिला थाने में दीपक हुड्डा पर हमले के वीडियो को स्वीटी बूरा ने एडिटेड और छेड़छाड़ कर जारी किया बताया था। इस पर वकील सागर पंघाल ने कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। स्वीटी बूरा वीडियो में साफ मारपीट करती दिख रही है। वकील ने स्वीटी बूरा को नसीहत देते हुए कहा कि दहेज के केसों के मामले कोर्ट में सुलझाएं जाते हैं ऐसे सोशल मीडिया पर आकर लाइव होकर कुछ भी कहने से केस नहीं लड़े जाते। दीपक हुड्डा और स्वीटी बूरा के बीच झगड़े की वजह बताने से सागर पंघाल ने इनकार कर दिया है सागर का कहना है कि मामला कोर्ट में है ।

1 मई से एटीएम से कैश निकालना महंगा होगा

आरबीआई ने विड्रॉल फीस 2 बढ़ाई, 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद चार्ज 21 से 23 हो जाएगा

न्यूज क्राइम फाइल

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने शुक्रवार को एटीएम विड्रॉल फीस बढ़ाने का ऐलान किया। नोटिफिकेशन के अनुसार, 1 मई से ग्राहकों को मंथली फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर हर ट्रांजैक्शन के लिए एडिशनल 2 रुपए का भुगतान करना होगा। अभी बैंक फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर 21 रुपए चार्ज करते हैं। अब 23 रुपए चार्ज करेंगे। इससे पहले आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस भी बढ़ाने का ऐलान किया था। एटीएम ने इंटरचेंज फीस भी 2 रुपए बढ़ाई है। यानी अब हर ट्रांजैक्शन पर 19 रुपए इंटरचेंज चार्ज देना होगा, जो पहले 17 रुपए था। बैलेंस चेक करने के लिए 7 रुपए चार्ज लगेगा वहीं नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन-जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी के लिए फीस को 1 रुपए बढ़ाया गया है। यानी अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए हर ट्रांजैक्शन पर अब 7 रुपए चार्ज लगेगा, जो पहले 6 रुपए था। एटीएम से कितने फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अलग-अलग बैंकों के एटीएम पर ग्राहकों को हर महीने लिमिटेड नंबर्स में फ्री ट्रांजैक्शन की अनुमति होती है। मेट्रो सिटीज में ग्राहकों को 5 ट्रांजैक्शन की अनुमति दी जाती है, जबकि नॉन-मेट्रो

सिटीज में 3 ट्रांजैक्शन की परमिशन है। यदि फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या पार हो जाती है, तो ग्राहकों को एडिशनल चार्जेस देना पड़ता है।

एटीएम इंटरचेंज फीस क्या है?

एटीएम इंटरचेंज फीस एक ऐसा चार्ज है, जो एक बैंक दूसरे बैंक को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए देता है। यह फीस आमतौर पर हर ट्रांजैक्शन पर लिया जाने वाला एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, जिसे अक्सर ग्राहकों को उनकी बैंकिंग कॉस्ट के हिस्से के रूप में जोड़ दिया जाता है। व्हाइट-लेबल एटीएम ऑपरेटरों की रिक्वेस्ट के बाद इन चार्जेस को रिवाइज करने का फैसला किया। एटीएम ऑपरेटरों ने तर्क दिया था कि बढ़ते ऑपरेशनल एक्सपेंस उनके बिजनेस को प्रभावित कर रहे थे। एटीएम चार्जेस में बढ़ोतरी पूरे देश में लागू होगी। इससे छोटो बैंकों के ग्राहक प्रभावित हो सकते हैं। ये बैंक एटीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर और इससे जुड़ी सर्विसेज के लिए बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर निर्भर होते हैं। यही वजह है कि बढ़ती लागत का प्रभाव ऐसे बैंकों पर ज्यादा होता है।

डिजिटल पेमेंट्स की वजह से एटीएम सर्विस पर प्रभाव पड़ा

भारत में डिजिटल पेमेंट्स की वजह से सर्विस पर प्रभाव पड़ा है। ऑनलाइन वॉलेट और ट्रांजैक्शन की सुविधा ने कैश विड्रॉल यानी नकद निकासी की आवश्यकता को काफी कम कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में वित्त वर्ष 2014 में 952 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के डिजिटल पेमेंट्स हुए थे।

बंगाल सरकार की घुसपैठियों पर दयादृष्टि के कारण ही सीमा पर फेंसिंग अधूरी है।

केंद्रीय गृहमंत्री-अमित शाह

कर्मण्येवाधिकारस्ते पर कहा-ऐसा कर्म ही क्यों करो, जिसकी चिंता करनी पड़े

सीएम बोले- नादान लोग गलत समझते हैं

न्यूज क्राइम फाइल

भोपाल में राजभवन के सभागार में बी ए कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, सीएम डॉ मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, उच्च शिक्षा विभाग के एसीएस अनुपम राजन, कमिश्नर निशांत बरवड़े मौजूद थे। सीएम ने मप्र में मिशन कर्मयोगी के लिए राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों को शामिल करते हुए एक कमेटी बनाने की घोषणा की। ताकि इसका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो।

काम का श्रेय कभी खुद न लें

मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे यहां एक शब्द प्रचलित है—ऋषि और मुनि। मुनि वे होते हैं, जो एक विशेष मार्ग का संकल्प लेकर अपनी आध्यात्मिक साधना में लीन रहते हैं और गृहस्थ जीवन अपनाने के बजाय एकाकी जीवन जीते हैं। वहीं, ऋषि गृहस्थ होते हुए भी अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देते हैं। वे न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ जीवन व्यतीत करते हैं और समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए हम विभिन्न रूपों में इनका योगदान देखते हैं—कभी वे वैज्ञानिक के रूप में, कभी आचार्य, तो कभी चिकित्सक के रूप में दिखाई देते हैं। जो भी कार्य करें, उसका श्रेय स्वयं लेने के बजाय समाज और सेवा की भावना को प्राथमिकता दें।

अपने कर्म का दोष भगवान को न दें - सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवद गीता में कर्म, अकर्म और विकर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। जिसने भी जन्म लिया है, उसके लिए सांस लेना, सोना और खाना भी कर्म है। हर व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा हुआ है। उन्होंने कहा, हम जो भी कार्य करें, उसका दोष भगवान

पर नहीं डाल सकते। यह कहना कि 'भगवान को ऐसा लगता है', सही नहीं है। भगवान को न तो कुछ लगता है और न ही वे किसी के कर्मों का दोष लेते हैं। सीएम ने कहा- हमने मप्र में 2020 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की लेकिन वर्तमान के दौर में जब भाषा की इस प्रकार की बातें आती हैं तो कोई बात नहीं, जिनको जैसी बातें करना वो राजनीतिक दृष्टि से करते होंगे। लेकिन, हम तो राष्ट्रनीति के आधार पर सोचते हैं।

बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय की अवधारणा ह्र के गठन से पहले से प्रचलित

मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे कर्म और आचरण हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जैसे जल से बर्फ बनती है, लेकिन बर्फ बनने के बाद जल कहां गया, यह नजर नहीं आता। जब बर्फ पिघलती है, तब जल फिर से प्रकट होता है। यह उदाहरण हमें यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि हम अपने कर्मों के आधार पर जहां भी पहुंचते हैं, वहां पूरी निष्ठा, ऊर्जा और आनंद के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा- यदि किसी खिलाड़ी का वजन किसी कारणवश घट या बढ़ जाता है तो चिंता की कोई बात नहीं। मेहनत जारी रखिए, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। कर्मयोग का यही सार है—निष्काम, निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। यह केवल कर्मचारी भाव से काम करने की बात नहीं है, बल्कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ राष्ट्र सेवा करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, हमारा जीवन केवल व्यक्तिगत स्वार्थ तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे राष्ट्र और राज्य के कल्याण से जोड़ना चाहिए। हमारी संस्कृति सदा से 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' की भावना पर आधारित रही है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ (ह) इस अवधारणा को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन हम इसे प्रारंभ से ही अपने आचरण में उतारते आ रहे हैं। इसी भाव के साथ हम विश्व कल्याण की बात भी करते हैं।

राज्यपाल बोले - 21वीं सदी भारत की होगी

कार्यशाला में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि राष्ट्र के भविष्य निर्माताओं के बीच चिंतन एक सही समय पर की गई महत्वपूर्ण पहल है। भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन, नेटवर्किंग, परिवहन सेवाओं के विस्तार, अर्थव्यवस्था की प्रगति, स्टार्टअप ईकोसिस्टम और क्लीन-ग्रीन इंडिया के माध्यम से दुनिया में एक नई पहचान और साख बनाई है। उन्होंने कहा कि इतिहास साक्षी है कि जापान, जर्मनी, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया चार-पांच दशक पहले ऐसे ही मोड़ पर खड़े थे, जहां से एकजुट होकर उन्होंने अपने राष्ट्र के विकास की नई इबारत लिखी। आज भारत भी उसी दौर से गुजर रहा है और हम मिलकर एक विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। राज्यपाल ने मानसिक तनाव और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों का जिक्र करते हुए कहा कि कर्मयोग जीवनदर्शन के अभ्यास से इन चुनौतियों से मुक्ति पाई जा सकती है। उन्होंने कर्मयोग की परिभाषा बताते हुए कहा कि व्यक्तिगत लाभ, सफलता-असफलता की चिंता किए बिना निरंतर कार्य करने वाला ही सच्चा कर्मयोगी होता है। हालांकि, इस पथ के अभ्यासी को शुरुआत में समाज की अपेक्षाओं, मान्यताओं और व्यस्त जीवनशैली जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन दृढ़ संकल्प से इन पर विजय पाई जा सकती है।

झंडा हटाने पर सीएमओ के मुंह पर कालिख पोती

न्यूज क्राइम फाइल

दमोह में धार्मिक ध्वज हटवाने के विरोध में भाजपा और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका सीएमओ के चेहरे पर कालिख पोत दी। इसके बाद चक्काजाम कर दिया। सीएसपी अभिषेक तिवारी मौके पर हैं, वे सड़क पर बैठे लोगों को समझा रहे हैं। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने सीएमओ को निलंबित करने की मांग की है। वे कलेक्ट्रेट में इसके लिए ज्ञापन देंगे। उनका कहना है कि हिंदू धर्म के विरोधियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। कलेक्टर सुधीर कोचर ने बताया, नवरात्रि

के शुभारंभ पर घंटा घर पर शुक्रवार रात हिंदूवादी संगठन द्वारा ध्वज लगाया जा रहा था। नपा कर्मचारियों ने उन्हें ऐसा करने से रोका। इस कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। कर्मचारियों का कहना था कि नपा सीएमओ के आदेश पर ऐसा किया गया है। इस मामले में संबंधितों को नोटिस जारी किया गया है। संगठन को भी अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है।

सीएमओ पर कार्रवाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। सकल हिंदू समाज के जिला अध्यक्ष कपिल सोनी ने भी इस कार्रवाई का विरोध किया। भाजपा नेता सतीश तिवारी ने बताया कि नवरात्रि के मौके पर हर साल की तरह घंटाघर की सजावट की जा रही थी।

मध्य प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव को जन्मदिवस की बहुत शुभकामनाएँ। वे मध्य प्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं। मैं ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य की और दीर्घायु होने की कामना करता हूँ।

रक्षा मंत्री-राजनाथ सिंह

सीएम ने भरी मीटिंग में 4 अफसरों को किया सस्पेंड

कहा- काम में देरी बर्दाश्त नहीं; सिवनी के टीआई-एसडीओपी को नोटिस

न्यूज क्राइम फाइल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भरी मीटिंग में 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। इनमें रीवा के तहसीलदार, मऊगंज नगर पंचायत के सीएमओ और सब-इंजीनियर भी शामिल हैं। सीएम ने कहा कि जो काम करना है, उसमें देरी बर्दाश्त नहीं। सीएम ने एफआईआर दर्ज नहीं करने के मामले में सिवनी के टीआई और एसडीओपी को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। सीएम डॉ. यादव ने शुक्रवार को मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन की बैठक ली। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों की समस्याओं के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं का लोगों को लाभ मिलने में देरी पर नाराजगी जताई। इस वर्चुअल बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आईजी, कमिश्नर और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सिवनी और सीहोर के अफसरों पर भी भड़के

सिवनी जिले में बच्चे, बच्चियों, महिलाओं के गुम होने और अपहरण के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने के मामले में टीआई और एसडीओपी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। सीहोर में नल जल योजना का पानी नल जल योजना समूह के लिए चिन्हित गांवों में से आखिरी गांव तक नहीं पहुंच रहा है। इस पर सीएम यादव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि- जब पानी दिए जाने का निर्णय है तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही है।

विदिशा, टीकमगढ़ और खंडवा के अफसरों पर सख्ती

विदिशा: मुद्रा योजना में लाभ नहीं दिए जाने पर सीएमओ को नोटिस दिया गया। साथ ही लीड बैंक मैनेजर के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए लीड बैंक को लिखा गया है।

टीकमगढ़: जिले में बकरी पालन के अनुदान की फाइल गायब हो गई थी। इस मामले में समाधान ऑनलाइन में मामला आने के बाद आनन फानन अनुदान दिया गया है।

खंडवा: दिव्यांगों को 193 दिनों से राशि नहीं मिलने पर कलेक्टर ने समाधान ऑनलाइन में मामला आने के बाद सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

7 करोड़ का घोटालेबाज शहर से हो गया फरार

गबन के बाद बहन के घर छिपा था संदीप; पत्र आया सामने, लिखा- सुसाइड कर रहा हूं

न्यूज क्राइम फाइल

जबलपुर के ऑडिट विभाग में पदस्थ रहे बाबू संदीप शर्मा ने सैलरी सॉफ्टवेयर में हेरफेर कर 7 करोड़ से अधिक का घोटाला किया। संदीप ने अपने विभाग प्रमुख से लेकर जिला कोषालय तक को ठग लिया। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट का फर्जी आदेश लगाकर भी उसने शासकीय विभाग के करोड़ों रुपए गबन कर लिए और किसी को खबर तक नहीं लगी। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के निर्देश पर ओमती थाना पुलिस ने संदीप शर्मा सहित विभाग के पांच अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। जिला कोषालय अधिकारी ने 13 मार्च को पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी। उधर, पुलिस का कहना है कि उसकी तलाश जारी है, वहीं सूत्रों के अनुसार, वह ग्वारीघाट स्थित सुखसागर वैली में अपनी बहन के घर पर छिपा हुआ था। मंगलवार को पुलिस जब तक वहां पहुंची, संदीप पहले ही फरार हो गया। इस बीच, संदीप शर्मा के नाम से एक पत्र भी सामने आया है, जिसमें उसने गबन की जिम्मेदारी लेते हुए आत्महत्या की बात लिखी।

संदीप शर्मा, बाबू

आरोपी संदीप शर्मा का पत्र आया सामने

संपरीक्षा विभाग में पदस्थ रहे संदीप शर्मा को 2012 में पिता की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। सॉफ्टवेयर संचालन में एक्सपर्ट संदीप ने बड़ी ही चालाकी से अपने अधिकारियों की नाक के नीचे करोड़ों का घोटाला कर दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। 25 फरवरी से गायब बाबू संदीप ने 2021 में इस फर्जीवाड़े की शुरुआत की थी और महज चार साल के भीतर 7 करोड़ रुपए से अधिक का गबन कर लिया। उसके गायब होने के बाद सोशल मीडिया पर उसका एक पत्र सामने आया है, जिसमें वह खुद को दोषी मान रहा है।

पत्र में सुसाइड करने की बात भी लिखी

मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। यह फैसला मेरा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोषी नहीं है। गलती मैंने की है, तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। सीमा मैम, प्रिया मैम, आदरणीय जेडी सर, इन सबकी आईडी और पासवर्ड मैंने गलत तरीके से उपयोग किए हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई भी रास्ता अब समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं, संदीप शर्मा, आत्महत्या कर रहा हूं। यह फैसला मेरा है, किसी का दबाव नहीं है। हो सके तो क्षमा करिएगा। परिवार वालों से नजर नहीं मिला सकता हूं, उनका मैं दोषी हूं...

संयुक्त संचालक समेत अन्य आरोपियों पर स्वद्रुक के बीच सामने आया पत्र

जैसे ही 7 करोड़ से अधिक के घोटाले का पर्दाफाश हुआ, संदीप ने कार्यालय आना बंद कर दिया। जब विभाग के अधिकारियों ने उसे फोन किया, तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। जहां वह रहता था, वहां पता किया गया तो जानकारी मिली कि वह घर पर नहीं है। इसी बीच, 13 मार्च को जबलपुर के ओमती थाना में पुलिस ने संदीप सहित विभाग के चार अन्य लोगों - संयुक्त संचालक मनोज बरहैया, सीमा अमित तिवारी, प्रिया विश्नोई और अनूप कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसके तुरंत बाद संदीप का पत्र सामने आया, जिसमें उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए आत्महत्या की बात लिखी थी।

बिहार की समृद्ध संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान और कला ने सदियों से भारत का मान बढ़ाया है और दिशा दिखाई है।

नेता प्रतिपक्ष-राहुल गांधी

सगाई में आए मेहमान की हत्या

बीच-बचाव करने पर हंसिया से किया वार, बेटी की शादी से पहले पिता गिरफ्तार

जबलपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर ग्राम देवरी में 51 वर्षीय व्यक्ति की हंसिया से हमला कर हत्या कर दी गई। मृतक का कसूर सिर्फ इतना था कि वह दो लोगों के बीच हो रहे विवाद को शांत कराने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान आरोपी ने उसके सिर और कंधे पर हंसिया से वार कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल व्यक्ति को ग्रामीणों ने तत्काल इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

आरोपी जंगल से गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही चरगंवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर गांव के जीवन सिंह ठाकुर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की गई। पुलिस ने शुक्रवार दोपहर आरोपी को गांव से सटे जंगल से गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

बेटी की सगाई में बुलाए गए थे ग्रामीण

42 वर्षीय आरोपी जीवन सिंह ठाकुर की बेटी की शादी तय हुई थी। बुधवार को सगाई (फलदान) के बाद गुरुवार को उसने गांव के कुछ बुजुर्गों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। इसी दौरान, गांव का कोदूलाल भी वहां पहुंचा, जिसका कुछ साल पहले जीवन सिंह से विवाद हो चुका था। ग्रामीणों की पहल पर मामला सुलझा लिया गया था, लेकिन भोज के दौरान दोनों के बीच फिर से कहासुनी हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को शांत कराया, लेकिन कोदूलाल गाली-गलौज करते हुए घर से बाहर आ गया। इसी बीच, जीवन सिंह गुस्से में हंसिया लेकर उसके पीछे दौड़ा। बीच-बचाव में

गई जान कोदूलाल को मारने के लिए भाग रहे जीवन सिंह को मौके पर खड़े अन्य ग्रामीणों ने रोकने की कोशिश की। इसी दौरान, मृतक भगत सिंह ठाकुर बीच-बचाव करने आया और हमले की चपेट में आ गया। हंसिया उसके सिर और कंधे में लगने से वह मौके पर गिर पड़ा। घटना के बाद भगत सिंह को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने कुछ घंटों में पकड़ा आरोपी

चरगंवा थाना प्रभारी अभिषेक प्यासी ने बताया कि आरोपी जीवन सिंह का कुछ साल पहले कोदूलाल से विवाद हुआ था, लेकिन ग्रामीणों ने सुलह करवा दी थी। अचानक हुए झगड़े में बीच-बचाव करने आए भगत सिंह की हत्या हो गई। पुलिस ने कुछ घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

शादी की खुशियां मातम में बदलीं

आरोपी जीवन सिंह की बेटी की शादी 20 दिन बाद होनी थी। घर में तैयारियां चल रही थीं, लेकिन इस घटना के बाद गांव में मातम छा गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

कांग्रेस देश में खत्म हो गई : कैलाश विजयवर्गीय

सागर में संविधान चौक के लोकार्पण में बोले मंत्री विजयवर्गीय, ई-लाइब्रेरी बनाने की घोषणा

न्यूज क्राइम फाइल

सागर में शुक्रवार को नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। उन्होंने शाम करीब 5.30 बजे धर्माश्री स्थित नवनिर्मित संविधान चौक का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश में पहला संविधान चौक सागर में बनाया गया है। मैं यहां से प्रेरणा लेकर जा रहा हूं। इंदौर के महापौर को बोलूंगा कि वह भी इंदौर में एक संविधान चौक बनाएं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हाथ में संविधान लेकर नाटक करने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जनता आपकी नौटंकी समझ चुकी है। अब यह सब नहीं चलने वाला है। कांग्रेस अब देश में खत्म सी हो गई है। क्योंकि उन्होंने हमेशा झूठ बोला, वादाखिलाफी की। उन्होंने हमेशा अनुसूचित जाति के लोगों

का शोषण किया। सिर्फ वोट बैंक बनाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गरीब की गरीबी दूर करने का संकल्प लिया है। आज हर गरीब के घर में 5 किलो अनाज पहुंच रहा है। कांग्रेस की हाथ में संविधान लेकर चलने वाली नोटंकी अब नहीं चलेगी।

सागर में बनेगी ई-लाइब्रेरी, डॉ. भीमराव अंबेडकर होगा नाम

कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री विजयवर्गीय ने घोषणा करते हुए कहा कि सागर में ई-लाइब्रेरी बनाई जाएगी। जिसके लिए मैं एक करोड़ देने की घोषणा करता हूं। उसमें सभी वर्ग के बच्चे आएंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करेंगे। इस ई-वाचनालय का नाम डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अंबेडकर भवन के पुर्ननिर्माण के लिए भी अगले तीन महीने में बजट देने का आश्वासन दिया है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि सागर में राजपूत समाज जहां चाहे वहां महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाई जाए। इस दौरान मंत्री ने कटरा बाजार में नगर निगम द्वारा बनाए गए डीडी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया।

राजधानी भोपाल स्थित मध्य प्रदेश विधानसभा में आयोजित युवा संसद 2025 में सहभागी बने मंदसौर जिले के ग्राम घसोई के होनहार छात्र श्री कपिल शर्मा से स्नेहिल भेंट की।
डिप्टी सीएम मप्र- जगदीश देवड़ा

रेलवे अफसर का बेटा बताकर धोखाधड़ी

युवक-महिला की जोड़ी ने 5 ज्वैलर्स को बनाया शिकार, साढ़े 7 लाख की चेन उड़ाई

न्यूज क्राइम फाइल

सतना में एक 55 वर्षीय महिला और 28 वर्षीय युवक की जोड़ी ने पांच ज्वैलरी शॉप पर धोखाधड़ी की। आरोपियों ने नकली सोना देकर असली सोना लेकर फरार हो गए। 27 मार्च को दोपहर एक बजे यह जोड़ी सबसे पहले राजेंद्र नगर स्थित आरती ज्वैलर्स पहुंची। यहां वजनदार चेन देखी और बदले में पुराना सोना दिया। इसी तरह मां शारदा ऑर्नामेंट रीवा रोड और संस्कार ऑर्नामेंट राजेंद्र नगर समेत दो अन्य शोरूम में भी ठगी की। इन सभी के यहां से लगभग साढ़े 7 लाख कीमत की ज्वेलरी साफ की। ठगों ने चालाकी से ऐसा सोना दिया, जिसमें ऊपर असली सोने की लेयर थी और अंदर नकली माल भरा था। अगले दिन जब दुकानदारों ने सोना गलाया, तब ठगी का पता चला। पीड़ित शिवांक सोनी ने बताया कि उनकी दुकान से करीब डेढ़ लाख रुपए की चेन ले गए। पीड़ित व्यापारियों ने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की निष्क्रियता के बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। सराफा संघ को जबलपुर में ठगों की लोकेशन मिली है।

खुद को बताया रेलवे अफसर का बेटा

पीड़ितों ने बताया कि ठगों के द्वारा काफी लंबी-चौड़ी बातें कही जा रही थीं। युवक के द्वारा अपना नाम चिराग शर्मा पिता जगदीश शर्मा बताया। उसने व्यापारी शिवांक को बताया कि उसके पिता रेलवे के अफसर हैं और हाल ही में उनकी यहां पोस्टिंग हुई है। चूंकि अभी क्वार्टर खाली नहीं हैं, इसलिए वे सिविल लाइन में किराए का मकान लेकर रह रहे हैं। अभी उन्हें और सोना लेना है इस बार कोई चेक नहीं देंगे पूरा कैश में खरीदेंगे।

जबलपुर में मिल रही लोकेशन

वहीं सराफा कारोबार से जुड़े व्यापारियों के ग्रुप में इस बात का मैसेज मिला है कि बंटी-बबली की लोकेशन जबलपुर में मिली है। जबलपुर के घामापुर स्थित मयूर ज्वेलर्स एवं राजकुमार ज्वेलर्स में शुक्रवार को यह जोड़ी देखी गई है। जिसकी सीसीटीवी फोटो सतना के सराफा कारोबारियों के ग्रुप में पोस्ट की गई है।

काली स्कार्पियो से देखे गए

ठगी के शिकार व्यापारियों के मुताबिक स्मार्ट सिटी के कैमरे में ये गिरोह काली स्कॉर्पियो क्रमांक क्र13 क्रा॥ 0002 में भी नजर आया है। लिहाजा अनुमान है कि गिरोह के बंटी और बबली ज्वेलर्स की दुकान में आते हैं और गिरोह के अन्य लोग आस पास स्कॉर्पियो में रहते होंगे।

हॉस्टल में 48 बच्चों के धर्मांतरण की कोशिश

मंडला में बाल आयोग ने धार्मिक किताबें की जब्त; बच्चे बोले-पास्टर और सिस्टर बनना चाहते हैं

न्यूज क्राइम फाइल

मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य मंडला के बिछिया जनपद में साइन फॉर इंडिया स्कूल की जांच करने पहुंचे। यहां ओडिशा का ज्योति राज बिना अनुमति स्कूल और छात्रावास चलाते मिला। जांच में सामने आया कि यहां मंडला, ओडिशा और अनूपपुर के 48 बच्चे रह रहे हैं। इनमें 15 लड़कियां और 33 लड़के शामिल हैं। इनके धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी। यहां से बड़ी मात्रा में धार्मिक किताबें भी जब्त की गई। टीम ने जब बच्चों से बात की तो उन्होंने बताया कि वे डॉक्टर और इंजीनियर नहीं, पास्टर और सिस्टर बनना चाहते हैं। यहां पेरेंट्स की अनुमति के बिना बच्चों को धार्मिक गतिविधियों में शामिल किया जा रहा था।

सभी बच्चों का धर्म क्रिश्चियन बताया

बाल संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. निवेदिता शर्मा ने बताया कि यहां स्कूल आवासीय स्कूल के रूप में संचालित हो रहा था। हॉस्टल में रह रहे 48 बच्चों के दस्तावेज पूरे नहीं मिले। यहां स्कूल के दस्तावेज में बच्चे का धर्म हिन्दू और जाति गोंड लिखी मिली। वहीं हॉस्टल के रिकॉर्ड में ईसाई बताया गया है।

डीपीसी बोले-बच्चों का ब्रेनवॉश किया जा रहा था

मंडला में डीपीसी केके उपाध्याय ने बताया कि संज्ञान में आया था कि स्कूल में धर्मातरंण की गतिविधियां चल रही है। गुरुवार रात 8 बजे हम जब वहां पहुंचे तो देखा 15 लड़कियां और 33 लड़के प्रार्थना कक्ष की ओर बाइबिल लेकर जा रहे थे। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वह प्रार्थना कक्ष में प्रार्थना करने जा रहे हैं। बच्चों ने बताया रोजाना शाम 6.30 से यहां ईसाई धर्म की प्रार्थना कराई जाती है। उन्होंने बताया कि पहले हम दूसरा धर्म मानते थे। लेकिन यहां आने के बाद हम ईसाई धर्म मानने लगे हैं। हम सब के भगवान एक है। यहां बच्चों के ब्रेनवॉश की प्रक्रिया चलाई जा रही है।

सभी बच्चों के धर्म को क्रिश्चियन बताया गया है। यहां बच्चियों के बाथरूम में कैमरे लगे हुए मिले जो आपत्तिजनक है।

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ 2025 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है, जिसकी बजटीय आवश्यकता 37,216.15 करोड़ है।
शिवराज सिंह चौहान-केंद्रीय कृषि मंत्री

सबसे गर्म साल होगा 2025

इस बार हीटवेव के दिन दोगुने होंगे; 5-6 की जगह लगातार 10-12 दिन लू चलेगी

संदीप कुमार सिंह

देश में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। भारतीय मौसम विभाग (ड्ढस्ठ) के मुताबिक, इस साल देश के नॉर्थ-वेस्ट राज्यों यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली में हीटवेव (लू) के दिनों की संख्या दोगुनी होने की आशंका है। आमतौर पर अप्रैल से जून के महीनों में लगातार 5-6 दिन लू चलती है, लेकिन इस बार 10 से 12 दिनों के ऐसे कई दौर आ सकते हैं। हालांकि, मौसम विभाग ने यह जानकारी नहीं दी कि इस साल हीटवेव का असर कितने दिन रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हीटवेव के दिनों की संख्या दोगुनी होती है तो 2025 अब तक का सबसे गर्म साल होगा। ऐसे में पारा सामान्य से 5 डिग्री या इससे भी ज्यादा रह सकता है।

हीटवेव के दिन गिनने का अलग तरीका

भारत के लिए साल 2024 सबसे ज्यादा गर्म सालों में से एक रहा था। बीते साल देश में 554 दिन हीटवेव का असर रहा था। बता दें कि साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन हीटवेव के लिए इन्हें गिनने का अलग तरीका है। मान लीजिए किसी महीने दिल्ली में 10 दिन, राजस्थान में 15 दिन, क्क में 12 दिन और बिहार में 8 दिन हीटवेव रही, तो हीटवेव डे 45 (10+15+12+8) माने जाएंगे। यानी उस महीने इन चार राज्यों में हीटवेव की कुल घटनाएं 45 हैं, न कि एक महीने में 45 दिन हीटवेव रही। ऐसे ही 2024 में 554 हीटवेव डे से मतलब देश में हीटवेव की कुल घटनाओं से है, न कि कैलेंडर के दिनों से। किस दिन को माना जाता है हीटवेव मैदानी, पहाड़ी और तटीय इलाकों के लिए हीटवेव की स्थिति तय करने का आधार अलग होता है। किसी दिन हीटवेव का असर तब माना जाता है जब उस दिनों के मौसम का तापमान सामान्य से 5 ज्यादा हो या... अगर तापमान सामान्य से 6.5 या उससे ज्यादा बढ़ जाए तो उसे गंभीर हीटवेव माना जाता है। IMD ने इस साल देश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान लगाया है। हीटवेव बढ़ने की 2 बड़ी वजह मौसम विभाग के मुताबिक, हीटवेव के दिन बढ़ने के पीछे की वजह अल-नीनो परिस्थितियां है। प्रशांत महासागर के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने से अल-नीनो परिस्थितियां बनती हैं। अभी देश के 8 राज्यों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा मौसम विभाग के मुताबिक, देश के 8 राज्यों का तापमान अभी 40 डिग्री से ज्यादा चल रहा है। मार्च से ही कई राज्यों में हीटवेव जैसी स्थितियां बनने लगी है। अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत में गर्मी और बढ़ सकती है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान 1-2 डिग्री तक बढ़ सकता है। हालांकि, उत्तर-पश्चिमी हवाओं यानी जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अगर बारिश या बर्फबारी हुई तो तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अगले तीन दिनों तक हवाएं चलेंगी, जिससे मौसम सूखा और धूलभरा रहेगा।

देश में गर्मी के मौसम को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है

1. प्री समर- मार्च और अप्रैल में गर्मी की शुरुआत होती है। अप्रैल के पहले सप्ताह से लू चलने के साथ ही गर्मी की शुरुआत मानी जाती है।
2. पीक समर- मई और मध्य जून में गर्मी पीक पर होता है। इस समय सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, जिससे पूरे देश में गर्मी तेजी से बढ़ने लगती है।
3. पोस्ट समर- जून के आखिरी सप्ताह से गर्मी थोड़ी कम होने लगती है। जैसे-जैसे मानसूनी हवाएं देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाती है, लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। कई बार मानसून चक्र में बदलाव की वजह से जुलाई महीने में भी भीषण गर्मी पड़ती है।

कैश मामला, जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर

नोटिफिकेशन जारी; सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर की मांग वाली याचिका खारिज

न्यूज क्राइम फाइल

केंद्र सरकार ने कैश मामले में घिरे दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का नोटिफिकेशन शुक्रवार को जारी कर दिया है। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चार्ज लेने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह आदेश जारी किया गया। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिया गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के जज के रूप में कार्यभार ग्रहण करने पर उन्हें कोई न्यायिक काम न सौंपा जाए। इससे पहले जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का वहां की बार काउंसिल ने विरोध किया था। वकीलों ने हड़ताल भी शुरू की थी। हाईकोर्ट के 6 बार काउंसिल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और कॉलेजियम के सदस्यों से मिलकर ट्रांसफर पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। इधर, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ स्न्रढ्ढक्र करने से इनकार करते हुए जनहित याचिका खारिज कर दी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा जज के घर नोटों से भरी बोरियां मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कमेटी जांच कर रही है। रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ मिला तो स्न्रढ्ढक्र होगी या फिर मामला संसद को भेजा जाएगा। जस्टिस वर्मा के घर में 14 मार्च को होली के दिन आग लग गई थी। फायर सर्विस की टीम जब उसे बुझाने गई तो स्टोर रूम में उन्हें बोरियों में भरे 500-500 रुपए के अधजले नोट मिले थे। तभी से यह पूरा मामला सुर्खियों में बना हुआ है। 34 साल पुराने फैसले को चुनौती दी गई जस्टिस वर्मा के खिलाफ स्न्रढ्ढक्र की मांग को लेकर एडवोकेट मैथ्यूज जे नेदुम्परा और तीन अन्य ने याचिका दायर की थी। याचिका में 34 साल पुराने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को भी चुनौती दी गई थी। 1991 में के वीरस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि CJI की परमिशन के बिना हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस शुरू नहीं किया जा सकता। उधर जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल से हटा दिया गया है।

जस्टिस वर्मा की जांच कमेटी के सामने इसी हफ्ते पेशी संभव

सुप्रीम कोर्ट की बनाई इन-हाउस कमेटी के सामने जस्टिस यशवंत वर्मा की पेशी इसी हफ्ते हो सकती है। समिति के समक्ष पेश होने से पहले बुधवार को सीनियर वकीलों से मुलाकात की। इनमें एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल, अरुंधति काटजू, तारा नरूला, स्तुति गुर्जर और एक अन्य जस्टिस वर्मा के घर पहुंचे। वकीलों ने जांच समिति के सामने दिए जाने वाले जवाबों को फाइनल करने में मदद की। दरअसल, जस्टिस वर्मा अपना फाइनल जवाब तैयार कर रहे हैं, यही आगे की कार्रवाई का आधार बनेगा।

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक उदय प्रताप सिंह चौहान द्वारा कविता ऑफसेट प्रिंटर्स, एमपी नगर जोन -1 भोपाल (म. प्र.) से मुद्रित एवं 1209 पुष्पा नगर चांदबड़, भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- उदय प्रताप सिंह चौहान, मो.7223003441 (प्रति सोमवार को प्रकाशित) समाचारों से संपादक का सहमत होना जरूरी नहीं। (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा।) RNI.NO MPHIN/2015/63623